International Journal for Multidisciplinary Research (IJFMR)
E-ISSN: 2582-2160 ● Website: www.ijfmr.com ● Email: editor@ijfmr.com

# देखभाल अर्थव्यवस्था एवं गृहणियां- सरकारी नीति

## डॉ. निभा कुमारी

पटना यूनिवर्सिटी, पटना- 800005, बिहार

**सार:**
देखभाल अर्थव्यवस्था (Care Economy) वह स्थान है जहां माँ की मेहनत रूप लेती है। यह अर्थव्यवस्था न केवल परिवारों की स्थिरता को बनाये रखती है बल्कि हमारे समाज और देश की आर्थिक वृद्धि में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। देखभाल अर्थव्यवस्था में उन सेवाओं को शामिल किया जाता है जो लोगों की देखभाल से जुड़ी होती है जैसे- बच्चों की देखभाल, बुजुर्गों की देखभाल, स्वास्थ सेवाएं एवं घरेलु कामकाज। ये कामकाज अकसर बिना किसी भुगतान के होते हैं और इनमें ज्यादातर महिलाएं जुड़ी होती हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में 92% महिलाएं बिना किसी भुगतान के घरेलू देखभाल कार्य करती हैं। भारत में महिलाएँ अपने कुल समय का 84% अवैतनिक देखभाल कार्य पर खर्च करती हैं। अदृश्य, अप्रतिदेय, तुच्छ समझे जाते और गैर-चिह्नित श्रम का यह भारी बोझ देश की देखभाल अर्थव्यवस्था (Care economy) की रीढ़ है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (International Labour Organisation) ने अपनी एक रिपोर्ट जारी की है, जिसके अनुसार विश्व की कुल जीडीपी का 9% ये अकेले देखभाल अर्थव्यवस्था है। देखभाल अर्थव्यवस्था में महिलाओं की भागीदारी पुरुषों की तुलना में 8 गुणा ज्यादा है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की रिपोर्ट में यह बताया गया कि यदि भारत की स्थिति के अनुसार भारत यदि अपनी जीडीपी का 2% देखभाल अर्थव्यवस्था पर खर्च कर लें तो देश में 11 मिलियन नए रोजगार का सृजन किया जा सकता है और इसमें 35% महिलाओं की भागीदारी होगीं। दूसरें दृष्टिकोण पर यदि ध्यान केंद्रीत किया जाये तो यह देखभाल आधारित अर्थव्यवस्था महिला सशक्तिकरण (महिलाओं को आर्थिक रूप से) संपन्न करने में भी अपना बड़ा योगदान दे सकती है।

**कीवर्डस:** देखभाल अर्थव्यवस्था, घरेलू कामकाजी महिला, अवैतनिक देखभाल, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, महिला सशक्तिकरण

## परिचय

सुबह से लेकर रात तक घरेलू महिला हर छोटी-बड़ी चीज़ का ध्यान रखती है, वह बच्चों की देखभाल करती है, घर का काम संभालती है, बुजुर्गों का ध्यान रखती है, एवं परिवार के लिए मजबूत आधार बनाती है. लेकिन क्या कभी हमने सोचा है की इस अनदेखी मेहनत का मूल क्या है? क्या हम इसे केवल एक पारिवारिक जिम्मेदारी समझकर नजरअंदाज कर सकते हैं?

देखभाल अर्थव्यवस्था (Care Economy) वह स्थान है जहां माँ की मेहनत रूप लेती है। यह अर्थव्यवस्था न केवल परिवारों की स्थिरता को बनाये रखती है बल्कि हमारे समाज और देश की आर्थिक वृद्धि में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। देखभाल अर्थव्यवस्था में उन सेवाओं को शामिल किया जाता है जो लोगों की देखभाल से जुड़ी होती है जैसे- बच्चों की देखभाल, बुजुर्गों की देखभाल, स्वास्थ सेवाएं एवं घरेलु कामकाज। ये कामकाज अकसर बिना किसी भुगतान के होते हैं और इनमें ज्यादातर महिलाएं जुड़ी होती हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में 92% महिलाएं बिना किसी भुगतान के घरेलू देखभाल कार्य करती हैं। भारत में महिलाएँ अपने कुल समय का 84% अवैतनिक देखभाल कार्य पर खर्च

करती हैं। अदृश्य, अप्रतिदेय, तुच्छ समझे जाते और गैर-चिह्नित श्रम का यह भारी बोझ देश की देखभाल अर्थव्यवस्था (Care economy) की रीढ़ है। देखभाल अर्थव्यवस्था अनौपचारिक अर्थव्यवस्था होती है, हम किसी को भी कभी भी काम पर रखते या निकालते हैं, उनका वेतन निर्धारित नहीं होता हैं। ये अर्थव्यवस्था दिखाई नहीं देती है इसलिए इसको हम अदृश्य अर्थव्यवस्था भी कहते हैं। कई बार हम पैसे के लिए कोई काम नहीं कर रहे हैं जैसे बुजुर्गो की देखभाल, बच्चों की देखभाल आदि अवैतनिक अर्थव्यवस्था में आती है। कई बार हम किसी को बहुत ही न्यून आय पर काम पर रख लेते हैं इसलिए इसको निम्न या अल्प आय अर्थव्यवस्था भी कहा जाता है। इन सन्दर्भों को निम्न प्रकार समझा जा सकता है-

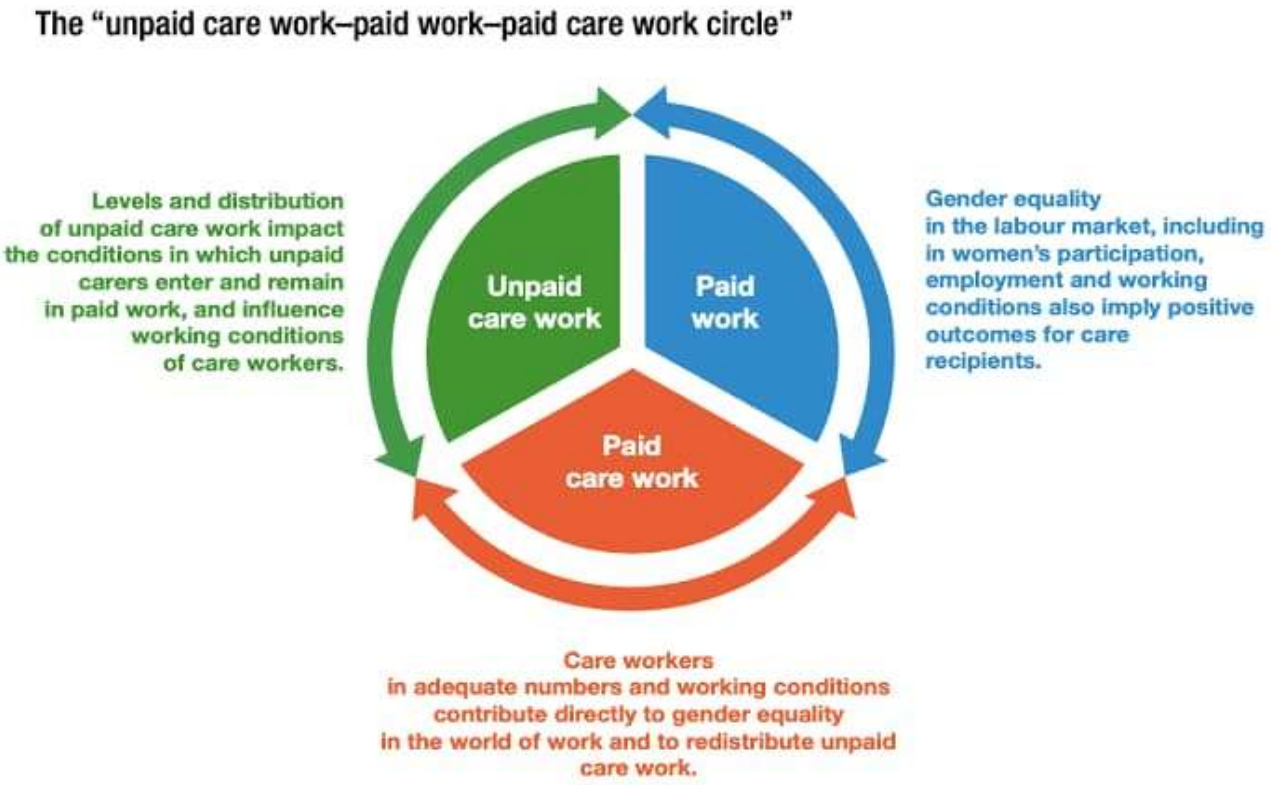


हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (International Labour Organisation) ने अपनी एक रिपोर्ट जारी की है, जिसमे उसनें एक सामानांतर अर्थव्यवस्था के बारे में बताया। इस रिपोर्ट के अनुसार जो हमारी औपचारिक अर्थव्यवस्था होती है उसकी तुलना में एक सामानांतर अर्थव्यवस्था भी चल रही है, जिसको इस रिपोर्ट में देखभाल अर्थव्यवस्था (Care Economy) का नाम दिया गया। इस रिपोर्ट के अनुसार जो विश्व की कुल जीडीपी का 9% ये अकेले देखभाल अर्थव्यवस्था है। देखभाल अर्थव्यवस्था में महिलाओं की भागीदारी पुरुषों की तुलना में 8 गुणा ज्यादा है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की रिपोर्ट में यह बताया गया कि यदि भारत की स्थिति के अनुसार भारत यदि अपनी जीडीपी का 2% देखभाल अर्थव्यवस्था पर खर्च कर लें तो देश में 11 मिलियन नए रोजगार का सृजन किया जा सकता है और इसमें 35% महिलाओं की भागीदारी होगीं। दूसरें दृष्टिकोण पर यदि ध्यान केंद्रीत किया जाये तो यह देखभाल आधारित अर्थव्यवस्था महिला सशक्तिकरण (महिलाओं को आर्थिक रूप से) संपन्न करने में भी अपना बड़ा योगदान दे सकती है।

वर्ष 2015 में संयुक्त राज्य संघ ने सतत विकास लक्ष्य (Sustainable Development Goal) घोषित किया जिसको 2030 तक प्राप्त करने का लक्ष्य तय किया गया। इसमें कुल 17 लक्ष्य घोषित किये गये।

सतत विकास लक्ष्य के **लक्ष्य क्रमांक 1 -** जिसमें गरीबी उन्मूलन (शून्य गरीबी) की बात की गयी है, **लक्ष्य क्रमांक 3-** (उत्तम स्वास्थ्य और खुशहाली) जिसमें स्वस्थ्य जीवन की परिकल्पना की गयी है, **लक्ष्य क्रमांक 4-** (गुणवत्तापूर्ण शिक्षा) जिसमें समावेशी शिक्षा की बात की गयी है, **लक्ष्य क्रमांक 5-** जिसमें लैंगिक समानता की बात की गयी है (महिलाओं के साथ भेदभाव ना हो), **लक्ष्य क्रमांक 8-** जिसमें उत्तम कार्य और आर्थिक वृद्धि की बात की गयी है। इस प्रकार यदि हम देखभाल अर्थव्यवस्था को अपना कर चलें तो जहाँ एक ओर यह आर्थिक सशक्तिकरण का माध्यम है वहीं सतत विकास लक्ष्यों को भी हासिल करने का माध्यम बन सकता है।

इंडिया केयर इकोनोमी: अन्लोकिंग अपोर्तुनिती, मार्च (2024) के एक रिपोर्ट के अनुसार, भारतीय समाज के दीर्घकालिक विकास और संतुलित विकास के लिए, देखभाल अर्थव्यवस्था के विकास को प्राथमिकता देने की आवश्यकता है - जो न केवल बच्चों की आबादी को कवर करती है, बल्कि 120 मिलियन से अधिक बुजुर्ग आबादी (60 वर्ष और उससे अधिक) और लगभग 30 मिलियन विकलांग लोगों को भी कवर करती है। भारत में देखभाल अर्थव्यवस्था का स्वस्थ विकास हमारे समाज में प्राथमिक देखभाल करने वालों का समर्थन करने के लिए आवश्यक है; जिनमें से अधिकांश हमारे

परिवारों में महिलाएँ हैं। यह नीति संक्षिप्त भारत भर में एक सुलभ, सस्ती और गुणवत्तापूर्ण देखभाल अर्थव्यवस्था के निर्माण की दिशा में एक प्रारंभिक - लेकिन महत्वपूर्ण - कदम है। उभरते बाजारों में भारत की महिला श्रम शक्ति भागीदारी दर सबसे कम है। भारत में कामकाजी उम्र (15-59 वर्ष) की चार में से केवल एक महिला या तो काम कर रही है या काम की तलाश कर रही है। यह देश भर में 57.3% पुरुष एलएफपीआर की तुलना में काफी कम है। महिलाओं के श्रम बाजार से बाहर होने का अक्सर एक प्रमुख कारण देखभाल के लिए पर्याप्त समर्थन की कमी है। टाइम-यूज़ सर्वे डेटा (2019) से पता चलता है कि भारत में कामकाजी आयु वर्ग की महिलाएं रोजाना लगभग सात घंटे अवैतनिक घरेलू काम में बिताती हैं। बच्चों और बुजुर्गों की देखभाल इस अवैतनिक घरेलू काम का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। भारत में महिलाओं के अवैतनिक घरेलू और देखभाल कार्यों का आर्थिक मूल्य सकल घरेलू उत्पाद का 15%-17% के बीच है। देखभाल अर्थव्यवस्था एक महत्वपूर्ण मूल्य है जो ज्यादातर घरों के भीतर ही निर्मित होता है और अक्सर इसे नजरअंदाज कर दिया जाता है क्योंकि ये गैर-विपणन योग्य लेनदेन होते हैं। भारत की देखभाल अर्थव्यवस्था में निवेश को अनलॉक करने के लिए कई कदम उठाने होंगे जो इस महत्वपूर्ण क्षेत्र के दीर्घकालिक विकास की नींव रखने के लिए आवश्यक हैं। जबकि सरकारों की इस संबंध में एक महत्वपूर्ण भूमिका है, यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि इस अर्थव्यवस्था का पहले से ही एक छोटा लेकिन तेजी से बढ़ता हुआ खंड है जो शहरी बाजार के कुछ वर्गों की सेवा करने वाले मजबूत राजस्व मॉडल पर फल-फूल रहा है। भारत के संवैधानिक प्रावधानों में महिलाओं से संबंधित अनेक प्रावधान हैं जैसे- **अनुच्छेद 14:** समता का अधिकार, **अनुच्छेद 15:** यह धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्मस्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध। **अनुच्छेद 16:** लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता की गारंटी देता है। यह महिलाओं को नियोजन से वंचित होने या उनके लिंग के कारण अलाभ का सामना करने से बचाता है। **अनुच्छेद 39 (1):** पुरुष और स्त्री सभी नागरिकों को समान रूप से जीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार, **अनुच्छेद 39 (4):** पुरुषों और स्त्रियों दोनों के लिये समान कार्य के लिये समान वेतन हो आदि। परंतु अनेक सरकारी नीति, संवैधानिक अधिकारों के बाबजूद देखभाल व्यवस्था पर इसकी उपयोगिता दूर दूर तक कहीं नहीं हैं।

**रोजगार पर प्रभाव-** देखभाल अर्थव्यवस्था का औपचारिकरण देश में रोजगार के नए अवसर उत्पन्न कर सकता है। यदि देखभाल कार्यों के लिए नीतिगत बदलावों किये जाये तो महिलाएं मौद्रिक अर्थव्यवस्था में अधिक सक्रिय रूप से भाग ले सकती हैं। जिससे देश की उत्पादकता बढ़ सकती है। ओईसीडी के एक रिपोर्ट के अनुसार महिलाओं की श्रम भागीदारी बढ़ने से जीडीपी में लगभग 27% की वृद्धि हो सकती है। देखभाल सेवाओं का औपचारिकरण, महिलाओं की श्रम भागीदारी बढ़ाना, सार्वजानिक निवेश बढ़ाना आदि के द्वारा हम देखभाल अर्थव्यवस्था मौद्रिक अर्थव्यवस्था में संतुलन बनाकर देश की प्रगति में योगदान किया जा सकता है। भारत की अर्थव्यवस्था के दीर्घकालिक विकास और भारत के समाज के संतुलित विकास के लिए देखभाल अर्थव्यवस्था का विकास महत्वपूर्ण है। सस्ती और गुणवत्तापूर्ण देखभाल न केवल भारत के राष्ट्र निर्माण के लिए मौलिक है, बल्कि भारतीय महिलाओं के पास मौजूद मानव पूंजी की पूरी क्षमता को उजागर करने की कुंजी भी है। **भविष्य में सभ्य काम के लिए भुगतान और अवैतनिक दोनों तरह के देखभाल कार्य आवश्यक हैं।** इसमें मुख्य रूप से दो अतिव्यापी गतिविधियाँ शामिल हैं: प्रत्यक्ष, व्यक्तिगत और संबंधपरक देखभाल गतिविधियाँ, जैसे कि बच्चे को खाना खिलाना; और अप्रत्यक्ष देखभाल गतिविधियाँ, जैसे कि खाना बनाना और सफाई करना। अवैतनिक देखभाल और घरेलू काम, जैसे कि बीमार साथी की देखभाल करना या परिवार के किसी सदस्य के लिए खाना बनाना, मौद्रिक मुआवजे के बिना प्रदान किया जाने वाला देखभाल कार्य है। भुगतान किया जाने वाला देखभाल कार्य - जैसे कि घरेलू कर्मचारियों द्वारा प्रदान की जाने वाली घरेलू सेवाएँ - किसी प्रकार के पारिश्रमिक के बदले में देखभाल करने वाले कर्मचारियों द्वारा किया जाता है। घरों और अर्थव्यवस्थाओं के संचालन के लिए अवैतनिक कार्य महत्वपूर्ण है, फिर भी सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) और आर्थिक विकास के अनुमानों में यह ज्यादातर अदृश्य और गैर-हिसाबित रहता है। मुख्य रूप से महिलाओं द्वारा किए जाने वाले देखभाल कार्य के कम मूल्यांकन और अदृश्यता के

परिणामस्वरूप बाजार की विफलता हुई है, जहां कुशल और प्रतिभाशाली महिलाएं अपनी आर्थिक क्षमता का एहसास करने में असमर्थ हैं, जिससे व्यापक आर्थिक स्तर पर संसाधनों का गलत आवंटन होता है। यह बाजार विफलता महिलाओं के लिए समय की कमी, महिलाओं की प्रतिभा का अकुशल आवंटन, देखभाल क्षेत्र में अच्छे वेतन वाली नौकरियों की कमी और मातृत्व दंड के रूप में प्रकट होती है, जो अंततः महिला श्रम शक्ति की भागीदारी को कम करती है और उनके आर्थिक विकास को बाधित करती है। देखभाल अर्थव्यवस्था में निवेश बढ़ाने से न केवल महिलाओं की श्रम शक्ति भागीदारी में लैंगिक अंतर को पाटने की क्षमता है, बल्कि उभरती अर्थव्यवस्थाओं के लिए एक नया आर्थिक खंड भी खुल सकता है, जिससे देखभाल कार्य सेवा क्षेत्र में आर्थिक उत्पादन और नौकरियों में वृद्धि हो सकती है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के साक्ष्य बताते हैं कि देखभाल सेवा क्षेत्र में बढ़ते निवेश से 2030 तक वैश्विक स्तर पर 475 मिलियन नौकरियां पैदा होने की संभावना है। भारत के लिए विशेष रूप से, सकल घरेलू उत्पाद के 2% के बराबर प्रत्यक्ष सार्वजनिक निवेश संभावित रूप से 11 मिलियन नौकरियां पैदा कर सकता है, जिनमें से लगभग 70% महिलाओं को मिलेंगी।

**मिनिस्टर फॉर विमेंस वेलफेयर, चाइल्ड एंड डेवलपमेंट एंड न्यूट्रीशन, गवर्नमेंट ऑफ़ उत्तरप्रदेश श्रीमती बेबी रानी मौर्या** ने कहा कि "महिलाओं द्वारा किए जाने वाले देखभाल कार्यों को मान्यता देना आवश्यक है, जिसमें बच्चों की देखभाल, घरेलू देखभाल और बुजुर्गों की देखभाल शामिल है। प्रबंधन और मल्टीटास्किंग में महिलाओं की अंतर्निहित शक्तियों को पहचाना जाना चाहिए और उनकी रोजगार क्षमता बढ़ाने के लिए उनका उपयोग किया जाना चाहिए, जिससे उन्हें सशक्त बनाया जा सके।"

**सीआईआई एनई काउंसिल के अध्यक्ष और नॉर्थ ईस्ट गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड के सीईओश्री एस. के. बरुआ ने कहा** "देखभाल क्षेत्र को पर्याप्त ध्यान और मान्यता की आवश्यकता है, क्योंकि इसकी बढ़ती मांग देश में हम जो जनसांख्यिकीय बदलाव देख रहे हैं, उससे स्पष्ट रूप से प्रमाणित होती है। अगले 30 वर्षों में बुजुर्गों और बच्चों की आबादी में उल्लेखनीय वृद्धि होने का अनुमान है, जो इस क्षेत्र के महत्व पर और अधिक जोर देता है।"

महिलाएं राष्ट्र की अर्थव्यवस्था मे योगदान देती हैं। इस अहम तथ्य के बावजूद गृहिणियों को पारंपरिक रूप से आर्थिक विश्लेषण से दूर रखा गया है। हमारा दायित्व है कि अंतरराष्ट्रीय कानूनों के अनुरूप इस मानसिकता में बदलाव किया जाए। लैंगिक समानता और महिलाओं की कार्यबल भागीदारी पर अवैतनिक देखभाल कार्य के प्रभाव पर विशेष रूप से ध्यान केंद्रित करते हुए, भारत में देखभाल अर्थव्यवस्था से जुड़ी चुनौतियों और अवसरों पर सरकार को विचार करना चाहिए।

## सन्दर्भ सूची:

1. https://static.pib.gov.in/WriteReadData/specificdocs/documents/2024/mar/doc202435319501.pdf
2. https://www.drishtiias.com/daily-updates/daily-news-editorials/india-s-care-economy
3. https://icrier.org/pdf/PB35-Care_Economy.pdf
4. https://www.civilsdaily.com/the-invisible-care-economy-does-budget-2025-recognize-the-its-contribution/
5. https://images.app.goo.gl/t63JeQQ6LZpmSD4y5
6. https://images.app.goo.gl/TJJrHHuWnYwnWTbY9
7. Formulating a Strategy for India's Care Economy: Unlocking Opportunities, March 2024, Bill&Melinda Gates foundation.